राजस्थान 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहा है- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित किया

जयपुर, 17 नवम्बर। सोमवार को फरीदाबाद में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देने के संकल्प के तहत, 22 जिलों में दिन में बिजली दे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में 2 हजार 215 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंजाब के राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली व लद्दाख के उपराज्यपाल तथा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 32वीं बैठक में भाग लिया।

साथ ही, आरडीएसएस के तहत, 33 केवी के 151 सब स्टेशनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में पुलिस मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ाने से औसत प्रतिक्रिया समय 21 मिनट से घटकर अब लगभग 13 मिनट पर आ गया है। इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय घटकर 58 दिन व बलात्कार प्रकरणों के निस्तारण का औसत समय घटकर 48 दिन रह गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा के तहत 88 प्रतिशत आबादी का कवरेज हो चुका है, जो देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म दूध पिलाया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान में सहकारिता में अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य ने भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है।

उन्होंने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने से राजस्थान को लाभ मिला है।

इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपस्थित थे।

'स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस गवई ने कहा कि यह उन्हीं (अध्यक्ष) पर निर्भर है कि वे इस मामले का फैसला करना चाहते हैं या अदालत की अवमानना का सामना करना चाहते हैं। यह अदालत की गंभीर अवमानना है। सीजेआई ने यह भी कहा कि अध्यक्ष को 31 अक्टूबर तक निर्णय लेना था।उन्होंने कहा, अगले सप्ताह तक फैसला कर दीजिए या अवमानना का सामना कीजिए। यह उन्हीं को तय करना है। हम पहले ही कह चुके हैं कि दसवीं अनुसूची से जुड़े मामलों में अध्यक्ष को संवैधानिक प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। उन्हें खुद तय करना होगा कि वह अपना न्यू ईयर ईव कहां बिताना चाहते हैं। गवई के सामने अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी अध्यक्ष की ओर से पेश हुए। सिंघवी ने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष दो सप्ताह के भीतर फैसला कर देंगे।

आतंकवाद को बढ़ावा जारी रखा तो सेना पाकिस्तान को सबक सिखायेगी

नयी दिल्ली, 17 नवम्बर। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने केवल ट्रेलर दिखाया था और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखता है तो सेना ने उसे यह सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है कि जिम्मेदार देश को अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा सेना को यह भी पता है कि बैरंग चिट्ठी का जवाब किसे देना है।

जनरल द्विवेदी ने सोमवार को यहां चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, "मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म शुरू भी नहीं हुई। सिर्फ़ ट्रेलर दिखाया गया। सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवादी या उनके आका हमारे लिए एक समान हैं। उन्होंने कहा कि सेना अब बैरंग चिट्ठी का जवाब देने के लिए भी तैयार है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में सतर्कता के लिए लगाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

केन्द्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया- पायलट

उन्होंने टोंक में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया

टोंक, 17 नवम्बर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्वभर में भारत के लोकतंत्र की मिसाल दी जाती थी।

पहले के समय में निर्वाचन आयोग पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, सरहद पर, जहां गांव-ढाणी में यदि एक, दो वोट ही होते थे, तो भी उन तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलकर जाता था, ताकि वहां रहने वाला एक भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रह जाये, इस भावना के साथ चुनाव आयोग काम करता था। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब संस्थाएं मजबूत होती हैं, परन्तु आज केन्द्र की भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं में सेंधमारी करके लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है।

- पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सक्रिय रहकर सतर्कता के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में प्रभावी भूमिका निभायें।

सचिन पायलट ने आज टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में सतर्कता के लिए लगाये गये कांग्रेस पार्टी के बीएलए के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कई राज्यों की मतदाता सूचियों की जांच करवाकर उनमें पायी गई त्रुटियों को उजागर किया है। ये त्रुटियां अनजाने में नहीं हुई हैं, ये जान-बूझाकर साजिशन की गई गलतियां हैं।

पायलट ने कहा कि हमें सक्रिय रहकर सतर्कता के साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

कार्यक्रम के बाद पायलट ने टोंक में नवनिर्मित गहलोद पुल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि गहलोद पुल, न्यू हॉस्पीटल सहित टोंक के वृहद प्रोजेक्ट निर्मित होकर तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन से कहा कि सरकार से आग्रह करके तैयार प्रोजेक्ट्स का शीघ्र लोकार्पण कर जनता को सुपुर्द करें।

नीतीश ने मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बता दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर "कोई दूसरा विचार" नहीं है। इस बात को साफ कर देने का उद्देश्य यह है कि किसी अंदरूनी खींचतान में या अंतिम समय पर किसी भाजपा नेता का नाम आगे बढ़ाने के दबाव की कोई गुंजाइश न रहे।

और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडीयू ने अगली गठबंधन सरकार बनाने के लिए भाजपा के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। इनमें शामिल हैं:

जेडीयू का स्पीकर पद पर दावा, जिसे विधानसभा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। जेडीयू के लिए एक उपमुख्यमंत्री पद, ताकि सरकार की संरचना में उसकी पकड़ मजबूत रहे।

बिहार के लिए तुरंत विशेष आर्थिक पैकेज, ताकि विकास संबंधी वादे और एनडीए के घोषणापत्र में दिये गए आश्वासन पूरे किए जा सकें।

ये मांगें जेडीयू के अंदर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती हैं, जिससे लगता है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने पार्टी को बड़ी चुनावी जीत दिलाई है, अब पहले की तरह भाजपा के दबाव में काम करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, नीतीश का इस्तीफ़ा न देना और भाजपा के साथ उनके बदलते समीकरणों ने संभावित राजनीतिक फेरबदल की अटकलों को तेज़ कर दिया है। महागठबंधन (एमजीबी), जिसने 35 सीटें जीती हैं, और एआईएमआईएम के पांच विधायक, दोनों ने ही नीतीश को खुली पेशकश की है कि यदि वे भाजपा से अलग होना चाहें तो उन्हें समर्थन दिया जाएगा।

हालांकि संख्या बल अभी भी एनडीए के पक्ष में है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि त्वरित एवं अप्रत्याशित रुप से पाला बदलने के इतिहास वाले नीतीश के लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। विपक्ष की समर्थन देने की पेशकश, भले ही अभी अनुमान पर आधारित है, लेकिन इससे भाजपा पर जेडीयू की बात मानने का दबाव और बढ़ गया है।

अपना इस्तीफ़ा रोककर रखने का नीतीश कुमार का फैसला साफ़ तौर पर चुनाव बाद की बातचीत में सौदेबाज़ी की ताकत बढ़ाने का समझा -सोचा तरीका लगता है। इस अनिश्चितता ने पटना में राजनीतिक माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है, जहां नीतीश के मित्र दल और विरोधी, दोनों ही उनके अगले कदम का इंतज़ार कर रहे हैं।

बिहार के हालात पर करीब से नज़र रखने वालों का मुख्य सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार एनडीए में अपनी अथॉरिटी और बढ़ा रहे हैं, या कोई बड़ा राजनीतिक खेल करने की तैयारी में हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मान्तरण विरोधी कानून पर राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा

यह नोटिस जयपुर कैथलिक वैलफेयर सोसायटी की याचिका पर जारी किया गया है

नयी दिल्ली, 17 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान गैरनानूनी धर्मांतरण निषेध कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जयपुर कैथोलिक वेलफैयर सोसाइटी की याचिका पर राज्य और अन्य से जवाब मांगा है। सोसाइटी की याचिका में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायालय को अवगत कराया, "हमने विधायी क्षमता के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में अधिकता का मुद्दा भी उठाया है।"

पीठ ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही शीर्ष न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस पर धवन ने कहा कि वर्तमान याचिका एक बिल्कुल अलग सवाल उठाती है। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे और दूसरे पक्ष को बुलाएंगे, और फिर हम आपकी बात सुनेंगे।"

अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।

मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।

- मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती दिए जाने पर 3 नवम्बर को भी राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा था।

गत 03 नवंबर को शीर्ष न्यायालय ने इसी कानून के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और राजस्थान सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा था। वर्ष 2025 का अधिनियम राजस्थान राज्य विधानसभा ने सितंबर में पारित किया था।

सितंबर 2025 में शीर्ष न्यायालय की एक अन्य पीठ ने भी कई राज्यों से उनके धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगे थे। न्यायालय ने कहा था कि जब संबंधित राज्य अपना जवाब दाखिल कर देंगे, उसे बाद ही ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के किसी भी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। लंबित याचिकाओं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में लागू किए गए मिलते-जुलते धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मामले पर सुनवाई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद होगी।

तेजस्वी को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया

पटना, 17 नवंबर। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने तेजस्वी प्रसाद यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया है।

राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि पार्टी की आज की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायक दल के नेता का पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें एक सुर से नेता चुन लिया।

यादव ने बताया को आज की बैठक में चुने हुए विधायकों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन को करीब एक करोड़ 85 लाख वोट मिले हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि मतदाताओं ने उसे नकारा नही है। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले सत्ता पक्ष ने अपनी लुभावनी योजनाओं और महिलाओं के खाते में पैसे भेज कर इसकी दिशा मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी पार्टी के 90 प्रतिशत उम्मीदवारों का जीत जाना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर नजर रखेगी और लोगों के बीच जा कर चुनाव आयोग के नकारात्मक कार्यों से जनता को अवगत कराएगी।

ट्रंप का दबाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का बचाव करते हुए कहा कि इस सौदे से पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की पारम्परिक निर्भरता कम होने की उम्मीद है, क्योंकि देश, बेहतर कीमतों की तलाश में आयात स्रोतों में विविधता लाने पर विचार कर रहा है।

भारत में घरों में एल.पी.जी. की बिक्री का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी पर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने एल.पी.जी. की पहुँच बढ़ाने के लिए गरीब और ग्रामीण परिवारों को गैस सुविधा देने पर जोर दिया है, ताकि वे परंपरागत और प्रदूषणकारी ईंधनों का उपयोग छोड़ सकें। अमेरिकी एल.पी.जी. के लिए यह टर्म डील ऐसे समय में हुई है, जब भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास में दोनों देशों के बीच ट्रेड सरप्लस कम करना चाहता है। व्यापार तनाव और भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के भारी आयात के बीच, डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने अधिकतर भारतीय सामानों पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिए थे। भारत और अमेरिका अब इन टैरिफ़ों को कम करने के प्रयास में बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन के साथ समझौता करने के लिए भारत अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ा सकता है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय रिफाइनरियों ने अमेरिका से तेल आयात बढ़ाया है, जिसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि व्यापार समझौते पर वार्ताओं के बीच नई दिल्ली और अधिक अमेरिकी ऊर्जा खरीदने के लिए तैयार है।

फरवरी में, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई, ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका, वॉशिंगटन को "भारत के लिए तेल और गैस का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता" बनाने की दिशा में कदम उठाने पर सहमत हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने में मदद मिल सकती है। ट्रंप ने यह भी जोड़ा था कि उम्मीद है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस आपूर्तिकर्ता बनेगा। नवंबर में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत ऊर्जा का बड़ा आयातक है और आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य में अमेरिका की "बहुत बड़ी भूमिका" होगी।

गोयल ने न्यूयॉर्क में "भारत-अमेरिका स्ट्रैटेजिक फ़ोरम" इवेंट में कहा था, "दुनिया मानती है कि ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हम सबको मिलकर काम करना होता है। भारत ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है। हम दुनिया भर से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ऊर्जा का बड़ा आयात करते हैं। हम आने वाले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार होने के नाते, हमारी ऊर्जा सुरक्षा में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।"

भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बडा उपभोक्ता है और उसकी लगभग 88 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती है। हमारा देश लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एल.एन.जी.) के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, हमारी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी मांग आयात से पूरी होती है। पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिका भारत के लिए कच्चे तेल का पाँचवाँ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता भी है। अगर एल.एन.जी. की बात करें तो भारत की 60 प्रतिशत से अधिक जरूरत आयात से पूरी होती है।

बांग्लादेश की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(आई.सी.टी.) का गठन, बिना किसी वैध अधिकार और अधिकार क्षेत्र के, मनमाने तरीके से किया है। उन्होंने आई.सी.टी. के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और इसे रद्द करने की मांग की है।

हसीना का कहना है कि अधिकारियों ने निष्पक्ष सुनवाई नहीं की और उन्हें अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया। जिस तथाकथित अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, उसमें किसी अंतरराष्ट्रीय न्याय संस्था का कोई प्रतिनिधि नहीं था और न ही उसका कोई कानूनी आधार था।

उन्होंने कहा कि यह ट्रिब्यूनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है, ताकि अंतरिम सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाया जा सके और छात्र आंदोलन के दौरान और उसके बाद हुए अत्याचारों के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सके। हसीना ने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी छात्र आंदोलनकारियों की हत्या के लिए कोई आदेश नहीं दिया।

आंदोलन, और हसीना के भारत आने के बाद देश में आगजनी, हत्या और अराजकता की लहर फैल गई थी। अवामी लीग के कई नेताओं और मंत्रियों पर हमले हुए और कुछ की बेरहमी से हत्या की गई। इमारतों को आग लगा दी गई और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। नए फैसले ने देश में अल्पसंख्यकों और अवामी लीग के प्रति निष्ठा रखने वाली राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक नेताओं पर हिंसा और हमले की आशंका बढ़ा दी है। देश संकट के कगार पर है और हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और राजनीतिक ताकतों के टकराव की आशंका है। जानकारों को यह भी भय है कि कट्टरपंथी इस्लामी तत्व फिर सक्रिय हो सकते हैं।

अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को अगली संसद की चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया है। यह वही पार्टी है, जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और लंबे समय से वहां की कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के हमलों का सामना कर रही है।

इन ताकतों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, शेख मुजीबुर रहमान, पर भी हमला किया था, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पाकिस्तान सरकार ने कैद कर रखा था। बाद में यही कट्टरपंथी समूह एकजुट हुए और मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या के बाद, सेना द्वारा तख्तापलट कराया गया।

मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के समय शेख हसीना भारत में थीं, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन अब यदि वे अपने देश लौटती हैं, तो उन्हें न्यायिक हत्या का सामना करना पड़ सकता है।

सऊदी अरब में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तेलंगाना सरकार ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पांच लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि घटना से जुड़े सभी आवश्यक समन्वय और प्रक्रियाओं के लिए राज्य की एक सरकारी टीम सऊदी अरब भेजी जाएगी। इस टीम का नेतृत्व राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अज़हरुद्दीन करेंगे। टीम में एआईएमआईएम के एक विधायक और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

मैडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर करोड़ों रूपए ठगने वाला गिरफ्तार

आरोपी खुद को नीट परीक्षा की सलैक्शन कमेटी का मैम्बर बताकर अभ्यार्थियों से पैसा ठगता था

जयपुर, 17 नवम्बर। श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार शातिर आरोपी अपने आपको नीट परीक्षा में सलेक्शन कमेटी का मेम्बर बता कर सम्पर्क करता था और रुपए वापस मांगने पर सीबीआई अफसर का फेक लैटर भेजकर धमकाता था। पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर अलवर जेल से गिरफ्तार करके लाई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में आरोपी विवेक कुमार उर्फ विनीत जोशी उर्फ राहुल उर्फ राहुल गुप्ता (32) निवासी सिवान बिहार, हाल में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) निवासी को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने पिछले दिनों आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर उसे अलवर जेल भेजा था। अलवर जेल में बंद जालसाज को श्याम नगर थाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जयपुर लेकर आई है।

- पुलिस के अनुसार, आरोपी विवेक कुमार के खिलाफ राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व मध्य प्रदेश में करोड़ों रूपए की ठगी के मामले दर्ज हैं।

राजस्थान के अलावा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम व मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ करोड़ों रुपए की ठगी के मामले दर्ज हैं। ठगी की रकम को वह 100 से अधिक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है। पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई गई है।

थानाधिकारी दलवीर सिंह ने बताया कि थाने में निर्माण नगर निवासी महेश चन्द अग्रवाल ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। मार्च, 2023 में उसके मोबाइल पर वॉट्सएप कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद का नाम विनीत जोशी बताते हुए कहा कि वह नीट के एग्ज़ाम में सलेक्शन कमेटी का मेम्बर है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हुए, कहा कि वह उसकी बेटी का एनआरआई कोटे की सीट पर कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन करवा देगा। सीट रिजर्व करने की कहकर जालसाज ने 5.50 लाख रुपए ऐंठ लिए। एडमिशन नहीं होने पर रुपए वापस मांगने पर वो सीबीआई ऑफिसर का फेक आईडी कार्ड लैटर भेजकर धमकाने लगा। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर अलवर जेल से गिरफ्तार किया।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर ड्रोन में संशोधन करके और घातक कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने का प्रयास करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी।

चुनावी हार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिनिधि की तरह चलाने में उनकी भूमिका पर है।

परिणाम आने के अगले दिन कुछ नेताओं की बैठक हुई, ये वही लोग थे, जो टिकट बांटने, बड़े फैसले लेने और खुद को पार्टी के मालिक की तरह पेश करने में शामिल रहे। इनमें अजय माकन, वेणुगोपाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे।

कल राहुल ने उन 12 राज्यों की बैठक बुलाई है, जहां एसआईआर लागू किया जा रहा है, और वहां के पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं को तलब किया गया है।

बिहार की हार से ध्यान हटाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि सीधे एसआईआर पर चर्चा शुरू कर दी जाए?

जबकि सबको पता है कि इन राज्यों में कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है और वह कुछ भी करने की हालत में नहीं है।

राज्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चंद्र शर्मा व अन्य ने खंडपीठ के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को खंडपीठ के फैसले पर यथा स्थिति के आदेश देते हुए प्रकरण को तीन माह में तय करने को कहा था। खंडपीठ में इन अभ्यर्थियों की अपील पर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908